Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

दिसंबर 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- इंदौर में होगा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट 3
- मध्य प्रदेश के दिव्यांग हिमांशु, दिव्यांग आयुक्त और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 4
- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 में आपराधिक पृष्ठभूमि के 90 विधायक विजेता 5
- अमरकंटक ताप विद्युत गृह एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार बना शतकवीर 6
- राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय 'बालरंग' महोत्सव 19 से 21 दिसंबर तक 7
- मध्य प्रदेश को वन्यजीव पर्यटन के लिये मिला 'सैंक्चुअरी एशिया अवॉर्ड' 7
- आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार ज़िले के तिरला विकासखंड को भारत के मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान 8
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन 9
- जीओसी सुदर्शन चक्र कोर ने दक्षिणी स्टार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना 9
- मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री 10
- डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में किया अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण 11
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 12
- सीएम डॉ. मोहन यादव को मिली Z+ की सुरक्षा 13
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ 14
- 20,000 करोड़ रुपए निवेश से बनेगी अटल मेडिसिटी, हर संभाग में मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस 15
- कूनो नेशनल पार्क में बनेगा देश का पहला 'चीता सफारी' 16
- राष्ट्रीय खेल सम्मान से अलंकृत होंगे मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी और 1 प्रशिक्षक 17
- जल महोत्सव का 8वां संस्करण 18
- मप्र उच्च न्यायालय में आईवीएसएस, कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास), ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ 19
- 1500 कलाकारों ने एक साथ किया तबला वादन, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज 20

नोट :

मध्य प्रदेश

इंदौर में होगा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर, 2023 को भारत में नेत्रहीनों के लिये क्रिकेट टूर्नामेंटों को संचालित करने वाली संस्था क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (कैबी) के चेयरमैन डॉ. महंतेश और जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव ने बताया कि 8 से 11 दिसंबर, 2023 तक इंदौर में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कैबी और समर्थनम् ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में इस चार दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
- टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया अगली ब्लाइंड भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिये खिलाड़ियों का चुनाव करेगी।
- टूर्नामेंट के आयोजक रितमित प्रोडक्शन के डायरेक्टर अमित आचार्य ने बताया कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य जोनल पुरुष टीमों को मंच प्रदान करना और देश में दिव्यांगजनों को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
- टूर्नामेंट में कुल 7 मैच आयोजित किये जाएंगे, जिसमें 4 जोन से कुल 70 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। टीमों को इंडिया ब्लू, इंडिया रेड, इंडिया ऑरेंज और इंडिया येलो कहा जाएगा।
- यह टूर्नामेंट न केवल दिव्यांगजनों के लिये, बल्कि सभी भारतवासियों के लिये बेहद खास है। इन असाधारण खिलाड़ियों ने साल 2012 और 2014 में वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड और 2017 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर देश को गौरवान्वित किया है।

नोट :

मध्य प्रदेश के दिव्यांग हिमांशु, दिव्यांग आयुक्त और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

3 दिसंबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के दिव्यांग हिमांशु कंसल, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त संदीप रजक और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, भोपाल को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिये विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिये 21 व्यक्तियों और 9 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया।
- श्योपुर ज़िले के कराहल गाँव के 100% श्रवणबाधित दिव्यांगजन हिमांशु कंसल को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने एवं उनके रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
- 'सुगम्य भारत अभियान' को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किये जा रहे कार्यों के लिये मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को 'सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधामुक्त वातावरण में सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य' श्रेणी में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने से संबंधित कार्य करने वाले संस्थानों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
- इसी प्रकार राज्य दिव्यांगजन आयुक्त संदीप रजक के द्वारा किये जा रहे कार्यों को मान्यता देते हुए 'दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 को अपने राज्य में कार्यान्वयन करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन' श्रेणी में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने से संबंधित कार्य करने वाले संस्थान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
- राज्य दिव्यांगजन आयुक्त संदीप रजक ने स्वत: अभिनव एवं प्रभावी कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कई मामलों में दिव्यांगजनों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1969 में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के रूप में उत्कृष्ट दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना को मंज़ूरी दी थी। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किये गए हैं।
- रास्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को उत्कृष्ट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये काम करने वाले व्यक्तियों/संगठनों को 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' पर प्रदान किये जाते हैं।
- वर्ष 2023 के लिये विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के तहत गए हैं-

I. विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार-2023-व्यक्तिगत उत्कृष्टता

- सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन
- श्रेष्ठ दिव्यांगजन
- लोकोमोटर चुनौती - (लोकोमोटर, मांसपेशीय चुनौतियाँ, बौनापन, एसिड अटैक विक्टिससुश्री, कुष्ठ रोग से उबरे हुए, सेरेब्रल पाल्सी)
- दृश्य हानि - (अंधापन, कम दृष्टि)
- श्रवण हानि (बहरा, सुनने में कठिनाई, बोलने और भाषा की चुनौती)
- बौद्धिक विकलांगता (मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट सीखने की चुनौती, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार)
- उपरोक्त उल्लिखित विकलांगताओं को छोड़कर कोई भी निर्दिष्ट विकलांगता।
  - श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका

नोट :

- सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति - दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये कार्यरत
- सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर (पुनर्वास पेशेवर/कार्यकर्ता) - दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत

II. दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार-2023

- दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)
- दिव्यांगों के लिये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता - (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)
- सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधामुक्त परिवेश के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/यूटी/ज़िला
- सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सरकारी/निजी संगठन)
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/यूटी/ज़िला
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त
- पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 में आपराधिक पृष्ठभूमि के 90 विधायक विजेता

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 में जीतने वाले विधायकों में 90 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनमें से 34 पर गंभीर अपराध दर्ज है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 में कुल विजेताओं में से 39 प्रतिशत अपराधी तो 15 प्रतिशत पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। भाजपा के 51, कॉन्ग्रेस के 38 और भारत आदिवासी पार्टी के एक विजेता ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- वर्ष 2018 में 94 विधायकों ने अपराध एवं 47 ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये थे। अर्थात कुल विजेताओं में से 41 प्रतिशत अपराधी तो 20 प्रतिशत पर गंभीर अपराध दर्ज थे।

- उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपें गए शपथ पत्र के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार विजेताओं में 205 करोड़पति हैं और इनकी औसत संपत्ति 11.77 करोड़ रुपए है। 2018 में विधायकों की औसत संपत्ति 10.17 करोड़ रुपए थी।
- पुन: निर्वाचित होने वाले 101 विधायकों की औसत संपत्ति में पाँच वर्ष में 4.60 करोड़ (37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 में तीन अधिक संपत्ति रखने वाले विजेता हैं- चेतन्य कश्यप (रतलाम सीट), संजय पाठक (विजयराघवगढ़) तथा कमलनाथ (छिंदवाड़ा)।
- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 में तीन सबसे कम संपत्ति रखने वाले विजेता हैं- कमलेश्वर डोडियार (सैलाना), संतोष वरकडे (सीहोरा), कंचन मुकेश तन्वे (खंडवा)।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार बना शतकवीर

चर्चा में क्यों?

5 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट ने 100 दिन सतत् उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। यह यूनिट इस वर्ष 27 अगस्त से लगातार विद्युत उत्पादन कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- इस यूनिट ने इससे पूर्व इस वर्ष 10 मई को भी 100 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने की उपलब्धि हासिल की थी। एक कैलेंडर एवं वित्तीय वर्ष में 210 मेगावाट की यूनिट ने दूसरी बार 100 दिन लगातार विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है।
- इस यूनिट ने जब 5 दिसंबर को दूसरी बार 100 सतत् विद्युत उत्पादन करने का कीर्तिमान अर्जित किया, तब इसने विभिन्न मापदंडों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। यूनिट ने 100.7 फीसदी पीएएफ, 99.14 फीसदी पीएलएफ एवं 9.14 फीसदी ऑक्जलरी खपत की उपलब्धि हासिल की। यह यूनिट वर्तमान में भी सतत् विद्युत उत्पादन कर रही है।
- पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने बताया कि कंपनी के थर्मल पॉवर प्लांट की वर्तमान में संचालित 12 इकाईयों में से यह ऐसी 9वीं यूनिट है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक दिनों से सतत् संचालित किया जा रहा है।

नोट :

राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय 'बालरंग' महोत्सव 19 से 21 दिसंबर तक

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग अरविंद चोरगढ़े ने बताया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 से 21 दिसंबर तक तीन दिवसीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय 'बालरंग' महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त संचालक अरविंद चोरगढ़े ने बताया कि 'राज्यस्तरीय बालरंग' में प्रदेश के सभी संभागों से लगभग 1000 छात्र-छात्राएँ एवं 'राष्ट्रीय बालरंग' में विभिन्न राज्यों के लगभग 500 छात्र-छात्राएँ सहभागिता करेंगे।
- इस वर्ष बालरंग महोत्सव की थीम 'आत्मनिर्भर भारत' होगी, जिसमें प्रदेश के छात्र-छात्राएँ अपने ज़िले की संस्कृति, वेशभूषा, नृत्य एवं खानपान आदि को विभिन्न मंचों पर प्रदर्शित करेंगे।
- लगभग 20 राज्यों से सहभागिता करने आ रहे छात्र-छात्राएँ अपने राज्य के लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय बालरंग में उत्कृष्ट लोकनृत्य के लिये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त नृतक दलों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- चोरगढ़े ने बताया कि राज्यस्तरीय बालरंग में सांस्कृतिक, साहित्यिक, योग, संस्कृत, निशक्तजन एवं मदरसा प्रतियोगिताएँ, राष्ट्रीय लोक नृत्य, लघु भारत प्रदर्शनी, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित क्रिएटिव क्राफ्ट, गतिविधि आधारित प्रदर्शनी एवं विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न ज़िलों एवं राज्यों के खाद्य पदार्थ (फूड जोन) की प्रदर्शनी और अन्य प्रतियोगिताएँ भी आयोजित होंगी।

मध्य प्रदेश को वन्यजीव पर्यटन के लिये मिला 'सैंक्चुअरी एशिया अवॉर्ड'

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड को टॉफ टाइगर्स वाइल्डलाइफ टूरिज़्म अवॉर्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ सतत् वन्यजीव पर्यटन राज्य' (द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्डलाइफ टूरिज़्म स्टेट) के लिये 'सैंक्चुअरी एशिया अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकृति, पर्यटन, उद्योग, सतत् प्रथाओं और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये पुरस्कृत किया गया है। टूरिज़्म बोर्ड की ओर से यह पुरस्कार उप-संचालक युवराज पडोले ने ग्रहण किया।
- समारोह में मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा प्रदेश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। ऑडियो-विज़ुअल प्रेज़ेंटेशन के माध्मय से मध्य प्रदेश के विभिन्न ऐतिहासिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, लोक एवं शिल्प कला एवं वन्यजीव पर्यटन पर आधारित जानकारी साझा की गई। अतुल्य भारत के दिल 'मध्य प्रदेश' को घूमने के लिये एक आकर्षक एवं आदर्श गंतव्य के रूप में चित्रित किया गया।
- प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज़्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का टाइगर स्टेट है और दुनिया से टाइगर्स को देखने के लिये पर्यटक यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों में पहुँचते हैं। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये वन्य क्षेत्रों के आस-पास ईको-फ्रेंडली होमस्टे, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यटकों में जागरूकता लाने जैसे विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।
- विदित हो कि मध्य प्रदेश वन्यजीवों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। 12 राष्ट्रीय उद्यानों और 24 वन्यजीव अभ्यारण्यों के साथ, विभिन्न पौधों, जानवरों और पक्षियों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
- देश में सर्वाधिक टाइगर्स मध्य प्रदेश में होने के कारण 'टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया' होने का गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 785 टाइगर हैं। इसके साथ ही प्रदेश को 'लेपर्ड स्टेट' और 'घड़ियाल स्टेट' का भी गौरव प्राप्त है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के आगमन से प्रदेश को 'चीता स्टेट' के रूप में मान्यता मिली है।

आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार ज़िले के तिरला विकासखंड को भारत के मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2023 को भारत सरकार के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार ज़िले के तिरला विकासखंड को भारत के मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर तिरला विकासखंड को 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम अंतर्गत देश के 329 ज़िलों के 500 विकासखंडों को सम्मलित किया गया है, जिसमे मध्य प्रदेश से चयनित 42 विकासखंड में धार ज़िले का विकासखंड तिरला भी शामिल है।
- नीति आयोग के निर्देशानुसार सर्वप्रथम विकासखंड द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन कर आकांक्षी विकासखंड को प्रेरणादायी विकासखंड में परिवर्तित करने के लिये नीति आयोग के मापदंडों पर रणनीति तैयार की गई।
- रणनीति तैयार किये जाने के उपरांत धरातल पर कार्यों को संपन्न किया जा रहा है, जिसे गति प्रदान करने के लिये 30 सितंबर, 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया।
- आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चयनित 500 आकांक्षी विकासखंडों में समस्त विभागों के कार्यों में गति प्रदान कर हितग्राहियों को लाभान्वित करना है।
- विदित हो कि मध्य प्रदेश ज़िला धार के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन और ज़िला पंचायत के सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन तथा जनपद पंचायत तिरला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिम्मी बाहेती के नेतृत्व में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत अधोसंरचना एवं सामाजिक विकास जैसे कुल पाँच मापदंडों पर ज़िला धार के विकासखंड तिरला ने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है।

नोट :

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को दिशा एवं मार्गदर्शन देने तथा उसकी मॉनिटरिंग के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, आदिम जाति कल्याण, सदस्य होंगे।
- कृषि आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया हैं। समिति विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सभी आवश्यक निर्णय लेगी।
- विकसित भारत संकल्प यात्रा की सतत् मॉनिटरिंग तथा फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये सात कोर समूह भी गठित किये गए हैं।
- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान कल्याण तथा कृषि, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व, सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, आयुक्त स्वास्थ्य, आयुक्त कृषि कोर समूह समय-समय पर प्रगति की समीक्षा कर राज्यस्तरीय स्टेयरिंग कमेटी को आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

जीओसी सुदर्शन चक्र कोर ने दक्षिणी स्टार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2023 को 263वें सेना सेवा कोर दिवस के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा परिवर्तन वर्ष के रूप में मनाने की भावना को ध्यान में रखते हुए, जीओसी सुदर्शन चक्र कोर ने द्रोणाचल, भोपाल से दक्षिणी स्टार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- इलेक्ट्रिक कारों के स्वदेशी निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा और प्रवेग की भागीदारी वाली इस रैली का उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बारे में जागरुकता फैलाना है।
- इस रैली को उपयुक्त रूप से 'ऑलिव ग्रीन गोज ग्रीन' थीम दी गई है। सागर, झाँसी, ग्वालियर, आगरा और मथुरा शहरों से गुजरते हुए रैली 800 किमी. की दूरी तय करेगी।
- रैली के सदस्य भारतीय समसामयिक विषयों पर जागरुकता के लिये विभिन्न सैन्य चौकियों में स्कूली बच्चों, दिग्गजों और सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे।
- ग्निवीर नामांकन योजना, मेक इन इंडिया, ग्राम सेवा देश सेवा एवं श्रीअन्न को बढ़ावा देने, स्वच्छ भारत हरित भारत और वेटरंस वी केयर सहित सेना की पहल को दर्शाएंगे।
- इस अवसर पर जीओसी सुदर्शन चक्र कोर ने पौधा रोपण किया और ओआईसी रैली को पौधे सौंपे, जिन्हें नई दिल्ली के अंतिम गंतव्य के रास्ते में विभिन्न सैन्य चौकियों में लगाए जाने की योजना है। ईवी रैली को अंतत: नई दिल्ली में डीजीएसटी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी।

मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

11 दिसंबर, 2023 को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उज्जैन दक्षिण सीट से तीसरी बार विधायक बने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के. लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था।
- मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। भावी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 13 या 14 दिसंबर को नई सरकार शपथ लेगी।

नोट :

- विधायक दल की बैठक में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उपमुख्यमंत्री चुना गया। इनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा।
- 58 वर्षीय मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। वह 2020 में शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। वह संघ में कई पदों पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं।
- विदित हो को 17 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद भाजपा को 163 सीटों पर जीत मिली थी।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में किया अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2023 को डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहुँचकर अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को राज्य शासन ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ. कुसमरिया ने आयोग की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
- मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्य रूप से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिये हितप्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही आयोग राज्य की सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जातियों की सूचियों में जातियों को जोड़ने एवं विलोपित करने की अनुशंसा राज्य शासन को भेजता है।
- कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ. कुसमरिया ने कहा कि वे शीघ्र ही ज़िलों का दौरा कर पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वे पिछड़ा वर्ग से जुड़े स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी दिक्कतों को समझेंगे और सुझाव प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिह्नित महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश के ज़िला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिह्नित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन किया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजीलॉकर में अपलोड किये जाने का निर्णय लिया गया।
    - उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। अभी तक कुल 09 शासकीय विश्वविद्यालयों एवं 5 निजी विश्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधिकांश डिग्री/अंकसूची डिजीलॉकर में दर्ज की जा चुकी है।
    - मंत्रि-परिषद द्वारा 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेश व्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे 'साइबर तहसील' नाम दिया गया है।
    - इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वत: ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है।

- वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 ज़िलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हज़ार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हज़ार रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हज़ार रुपए प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

- उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2017 में 1250 रुपए प्रति बोरा थी, जिसे वर्ष 2023 में बढ़ाकर 3 हज़ार रुपए प्रति बोरा कर दिया गया था।
- मंत्रि-परिषद द्वारा धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में प्राप्त जमानत सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त करवाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाईसेंस के खुले में अवैध रूप से माँस-मछली आदि का क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया।

सीएम डॉ. मोहन यादव को मिली Z+ की सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- जेड प्लस सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में 36 NSG कमांडो तैनात होंगे। इसके साथ ही 2 एसपी, 2 एएसपी और 4 डीएसपी, विशेष सुरक्षा बल के जवान और राज्य पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात किये जाएंगे।
- सीएम डॉ. मोहन यादव के लिये 15 से 18 गाड़ियों का काफिला होगा। इस काफिले में एक बुलेटप्रूफ कार भी शामिल हैं, जिसमें वह सवार रहेंगे।
- गौरतलब है कि भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की सुरक्षा श्रेणियाँ हैं: एक्स (X), वाई (Y), जेड (Z) और जेड प्लस (Z Plus)। इसके अतिरिक्त SPG सुरक्षा भी है, जो केवल प्रधानमंत्री और उसके परिवार के लिये होती है। अन्य सुरक्षा श्रेणियों के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जिस पर खतरे की आशंका के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों के पास खतरे से जुड़ी कोई जानकारी हो।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

17 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर ज़िले के ग्राम रानीपुरा में निर्मित की गई कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट (टेंट सिटी) में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक किया जा रहा है।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास बसाई गई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी में हो रहे इस महोत्सव द्वारा क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- कूनो फॉरेस्ट रीट्रीट (टेंट सिटी) में पर्यटक लग्जरी ग्लेम्पिंग का आनंद ले सकेंगे। साथ ही पर्यटक हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, जंगल सफारी जैसी गतिविधियों से खुद को रोमांचित कर पाएंगे।
- इयाक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और लल्लूजी एंड संस द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रोमांचक गतिविधियों का अनूठा अनुभव भी मिलेगा। स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रचारित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यशालाएं भी होंगी।
- यह फेस्टिवल रोमांच, मनोरंजन और संस्कृति का तालमेल होगा। जंगल सफारी में क्षेत्र की समृद्ध वन्यजीव संपदा को देखने का मौका भी मिलेगा। पारंपरिक कला, सांस्कृतिक आयोजनों और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को प्रचारित भी किया जाएगा।
- 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के साहसिक खेल, कला, शिल्प, संगीत ग्राम भ्रमण, भोजन सहित अनेक गतिविधियां आयोजित होंगी। पर्यटकों के लिए एक टेंट सिटी तैयार की गई है, जिसमें 50 सर्व सुविधायुक्त स्विस टेंट लगाए गए हैं।
- पर्यटक यहां पैरा सेलिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, साइलेंट डीजे ऑन साइट के साथ स्टार गेजिंग, जंगल सफारी, देव खोह भ्रमण तथा नाइट वॉक के अनुभव का आनंद ले सकेंगे।

नोट :

20,000 करोड़ रुपए निवेश से बनेगी अटल मेडिसिटी, हर संभाग में मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस

चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश जन संपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से मध्य प्रदेश निरामय इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में अटल मेडिसिटी स्थापित की जाएगी और प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 में हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 में दी गारंटी को पूरा करने के लिये सात दिन में रोडमैप बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये हैं।
- संकल्प पत्र के अनुसार प्रमुख शहरों में कैंसर रोगियों के लिये पैलियेटिव केयर सेंटर स्थापित किये जाएँगे।
- 'वन लोकसभा-वन मेडिकल कॉलेज' योजना के अंतर्गत हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाएँगे। 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन नर्सिंग कॉलेज' योजना में हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज होगा। 'वन ब्लॉक-वन ब्लड बैंक' योजना में हर ब्लॉक में ब्लड बैंक बनाए जाएँगे।
- एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या तथा अस्पताल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या को दोगुना किया जाएगा।
- विदित हो कि वर्तमान में प्रदेश में 132 प्रकार की जाँच निशुल्क उपलब्ध हैं। हर दिन लगभग 10,000 मरीज इसका लाभ उठा रहे हैं।
- साढ़े तीन वर्षों में 800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और विकास किया गया है। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 2,000 से 42,000 हो गई है और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या 10 गुना से ज़्यादा बढ़ाकर 2,085 की गई है।
- स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिये 11,000 से अधिक 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' शुरू किये हैं। प्रदेश में 2,000 से अधिक एंबुलेंस उपलब्ध हैं। डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या 7 गुना से ज़्यादा बढ़ाकर 51,000 से अधिक की गई है।
- आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिये पाँच लाख से ज़्यादा खर्च होने पर अतिरिक्त खर्च 'सीएम रिलीफ फंड' से किया जाएगा। निजि अस्पतालों में अत्यधिक चिकित्सा शुल्क को नियंत्रित करने के लिये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी।

नोट :

- पूरे प्रदेश में 500 नए जन औषधि केंद्र शुरू किये जाएँगे। इनमें कम कीमत पर दवाइयाँ मिलेंगी।
- वर्ष 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो वर्तमान में 24 हो गए हैं। एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई हैं। अगले पाँच सालों में 2,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएँगी।
- रेयर डिजीज के रोगियों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के अलावा भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। टीबी रोगियों को 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कूनो नेशनल पार्क में बनेगा देश का पहला 'चीता सफारी'

चर्चा में क्यों?

19 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अब 'चीता सफारी' बनाया जाएगा। यह देश का पहला 'चीता सफारी' होगा।

प्रमुख बिंदु:

- कूनो नेशनल पार्क में 'चीता सफारी' बनाने की अनुमति के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को पत्र भेजा गया था, जिस पर अब सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मुकुंदपुर की 'सफेद बाघ सफारी' की तरह यहां भी पर्यटक चीता सफारी का आनंद ले सकेंगे।
- कूनो नेशनल पार्क में एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, ताकि पर्यटक भ्रमण कर चीतों के विषय में जानकारी हासिल कर सकें। साथ ही कूनो नेशनल पार्क में उपलब्ध विभिन्न जानवर, पक्षी आदि के विषय में भी पर्यटकों को बताया जाएगा।
- शुरुआती आकलन में चीता सफारी के निर्माण की लागत 50 करोड़ आंकी गई है। इसके निर्माण में दो वर्ष का समय लग सकता है। 'चीता सफारी' का क्षेत्र 181.17 हेक्टेयर होगा, जिसमें 124.94 कूनो वनमंडल का वन क्षेत्र होगा। सफारी में 4 से 6 चीते छोड़े जाएंगे।
- इस प्रोजेक्ट को चीता सफारी कम टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कम इंटरप्रिटेशन सेंटर (चीता सफारी सह पर्यटक सुविधा केंद्र सह व्याख्या केंद्र) नाम दिया गया है।
- विदित हो कि कूनो नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए म.प्र. पर्यटन बोर्ड की ओर से कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसके लिए रानीपुरा में निजी कंपनी ने टेंट सिटी तैयार की है, जिसमें हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, जंगल सफारी जैसी गतिविधियां होंगी।

राष्ट्रीय खेल सम्मान से अलंकृत होंगे मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी और 1 प्रशिक्षक

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के तीन खिलाड़ियों का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए और एक प्रशिक्षक का चयन द्रोणाचार्य पुरूस्कार के लिए किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु 9 जनवरी, 2024 को राष्ट्रपति भवन में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरूस्कार से सम्मानित करेंगी।
- विदित हो कि पहली बार मध्य प्रदेश के तीन खिलाड़ियों और एक प्रशिक्षक को राष्ट्रीय खेल सम्मान से अलंकृत किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ओलंपिक खिलाड़ी एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पेरा कनोइंग की प्राची यादव और मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी की पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में हॉकी इंडिया की स्टार प्लेयर सुशीला चानू को राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ठ खेल पुरूस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के कोच शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरूस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर – मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार शूटर एश्वर्य इस वर्ष संपन्न हुए एशियन गेम्स में सबसे सफल भारतीय एथलीट थे। उन्होंने एशियन गेम्स में दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया। साथ ही एश्वर्य प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम किया और 50 मी. रायफल थ्री पॉजीशन पुरूष एकल इवेंट में रजत पदक जीता।
- प्राची यादव – मध्य प्रदेश की पेरा केनो प्राची यादव ने हाल ही में आईसीएफ स्प्रिंट एंड पेरा केनो वर्ल्ड चैंपियनशिप, जर्मनी में चौथा स्थान प्राप्त कर पेरिस पेरा ओलंपिक के लिये क्वालिफाई किया। प्राची भारत की पहली एथलीट है जिन्होंने पेरिस पेरा ओलंपिक के लिये कोटा हासिल किया है।
- सुशीला चानू – मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की पहले बैच की उत्कृष्ठ खिलाड़ी सुशीला ने कई उपलब्धियाँ हासिल की है। जर्मनी में हुए विमेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सुशीला की कप्तानी में कांस्य पदक हासिल किया था। 2014 एशियन गेम्स में उन्होंने भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2016 रियो ओलंपिक में सुशीला भारतीय टीम की कप्तान थी।
- शिवेंद्र सिंह – मध्य प्रदेश के शिवेंद्र सिंह वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल है। उन्होंने लगभग 160 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले है और लगभग 80 गोल अपने नाम किये है।

नोट :

जल महोत्सव का 8वां संस्करण

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2023 को खंडवा ज़िले के इंदिरा सागर बांध के जलाशय में जल पर्यटन के लिए देशभर में प्रसिद्ध हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हो गया। महोत्सव का समापन 20 फरवरी को होगा।

प्रमुख बिंदु

- कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल महोत्सव की शुरुआत की।
- नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के बेकवाटर में बसे निमाड़ का सिंगापुर कहे जाने वाले हनुवंतिया में दो माह तक पर्यटक टेंट सिटी, वाटर स्पोर्ट्स और जल, थल तथा आकाश की रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे।
- प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि यादगार और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए भव्य टेंट सिटी स्थापित की गई है। टेंट सिटी हनुवंतिया के सुंदर दृश्यों के बीच पर्यटकों को एडवेंचर एक्टिविटीज करने के बाद आराम करने और अपनों के साथ समय व्यतीत करने का बेहतरीन अवसर देंगे।
- कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ कई तरह की वैलनेस एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जायेगा जो मध्य प्रदेश के मिनी गोवा में आये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा।
- वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज, पर्यटकों को रोमांचक और अद्वितीय अनुभव से सराबोर कर देंगे। जेट स्की, स्पीड बोट, बनाना राइड, बंपर राइड, हॉट एयर बैलून, लैंड पैरासेलिंग, पैरा मोटर, रिवर्स/इजेक्शन बंजी आर्चरी, बोट एवं वाटर एक्टिविटीज, एटीवी बाइक राइड, आइलैंड पर ट्रेकिंग - हाइकिंग, हाई रोप कोर्स, जिप लाइन, ज़ोरबिंग (वाटर एक्टिविटी), एयर गन शूटिंग, वॉल क्लाइंबिंग और अन्य गतिविधियों का आनंद पर्यटक ले सकेंगे।
- उल्लेखनीय हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा सनसेट डेजर्ट कैंप के सहयोग से जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उच्चतम मानक अनुसार व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

मप्र उच्च न्यायालय में आईवीएसएस, कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास), ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

21 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आम नागरिकों की सहूलियत के लिये एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस), कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास) तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उच्च न्यायालय जबलपुर में वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम-क्लास परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं।
- यह देश में पहली बार है, जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में सभी ज़िला और तहसील अदालतों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है।
- यह अपने आप में देश की एक अग्रणी परियोजना है जो पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को अपनाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिम्मेदार नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अन्य अदालतों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
- यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक अग्रणी तकनीकी परियोजना है जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और उनका एकीकरण मध्य प्रदेश न्यायपालिका को डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा।
- वर्तमान स्थिति में, वर्चुअल कोर्ट रूम एक वास्तविक आवश्यकता है और यह परियोजना उस दिशा में एक कदम है। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ मामलों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कानून की शिक्षा में एक शक्तिशाली उपकरण होगी और आने वाले दशकों में लाखों कानून के छात्रों को लाभ पहुंच सकती है, किसी भी अदालत कक्ष को इंटरनेट पर लाइव देखा जा सकता है।
- पायलट चरण के तहत, जबलपुर में एक केंद्रीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (सीसीसी) और इंदौर में आपदा रिकवरी साइट स्थापित की गई है। जबलपुर के ज़िला न्यायालय और पाटन और सिहोरा के तहसील न्यायालयों में एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) चालू की गई है। इसी प्रकार, जबलपुर ज़िला न्यायालय के एक न्यायालय कक्ष और पाटन और सिहोरा के प्रत्येक तहसील न्यायालय के एक न्यायालय कक्ष में कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है।

नोट :

- परियोजना के राज्यव्यापी क्रियान्वयन के बाद के चरण दिसंबर 2024 तक पूरे होने की उम्मीद है। आईवीएसएस एवं क्लास परियोजना के क्रियान्वयन से न्यायालयों की सुरक्षा मजबूत होगी।
- आईवीएसएस और क्लास-
- एकीकृत वीडियो प्रबंधन प्रणाली।
- कोर्ट रूम ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम।
- संग्रह और लाइव के साथ-साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप।
- जबलपुर में डेटा सेंटर एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना।
- इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप।
- सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और संचालन एवं रखरखाव।
- वर्ष की अवधि के लिए परियोजना की कुल लागत 189.25 करोड़ रुपए होगी।

1500 कलाकारों ने एक साथ किया तबला वादन, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर 1500 से अधिक तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन की प्रस्तुति देकर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया।

प्रमुख बिंदु

- इस आयोजन को ताल दरबार का नाम दिया गया।
- इस आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
- इस आयोजन में दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लगभग 50 शहरों से लगभग 1500 से अधिक कलाकारों ने अपनी कला का एक साथ प्रदर्शन किया।
- विदित हो कि ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। यह इस समारोह की कड़ी में 99वाँ संस्करण था।